नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 074
दि. 16.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

तमिलनाडु और असम में चुनावी रण के लिए भाजपा ने बदली रणनीति

नए प्रभारियों की नियुक्ति से संगठन को धार देने की कोशिश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व ने दोनों राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारियों की नई सूची जारी करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि अब पूरा फोकस इन अहम चुनावों पर रहने वाला है। तमिलनाडु में चुनावी रणनीति की कमान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई है, जबकि अब तक तमिलनाडु के प्रभारी रहे बैजयंत पांडा को वहां से हटाकर असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पार्टी अलग-अलग राज्यों में नेतृत्व और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को नए सिरे से संतुलित कर रही है।

तमिलनाडु में पीयूष गोयल की नियुक्ति के साथ ही संगठन को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह-प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ पहले से सह-प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे मुरलीधर मोहोल भी टीम में बने रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में लगातार कमजोर प्रदर्शन और द्रविड़ राजनीति के दबदबे को देखते हुए भाजपा इस बार आक्रामक और दीर्घकालिक रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। केंद्र सरकार के अनुभवी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि तमिलनाडु उसके लिए केवल प्रतीकात्मक राज्य नहीं, बल्कि गंभीर राजनीतिक चुनौती और अवसर दोनों है।

दूसरी ओर असम में भी भाजपा ने चुनावी प्रबंधन को धार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। असम में भाजपा पहले से सत्ता में है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में पार्टी की कोशिश सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने और 2026 में फिर से मजबूत जनादेश हासिल करने की है।

तमिलनाडु की बात करें तो यहां कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर शानदार जीत दर्ज की थी। डीएमके ने अकेले 159 सीटें जीतकर दस साल बाद सत्ता में वापसी की थी और एम. के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में भी डीएमके-कांग्रेस गठबंधन ने राज्य की सभी 39 सीटों पर कब्जा जमाया, जिससे भाजपा के लिए राज्य में चुनौती और बढ़ गई। ऐसे में भाजपा नेतृत्व मानता है कि संगठनात्मक मजबूती, जमीनी स्तर पर विस्तार और नए चेहरे ही तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति सुधार सकते हैं।

असम में राजनीतिक स्थिति थोड़ी अलग है। यहां विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 75 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी और हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को लगभग 50 सीटें मिली थीं। अब 2026 में एक बार फिर सभी 126 सीटों पर चुनाव होंगे और भाजपा सत्ता बचाने के साथ-साथ अपना जनाधार और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और केंद्र-राज्य सरकारों की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर असम में जीत दोहराई जा सकती है।

कुल मिलाकर, तमिलनाडु और असम के लिए प्रभारियों में किए गए बदलाव भाजपा की उस रणनीति को दर्शाते हैं, जिसके तहत वह अगले साल होने वाले पांच विधानसभा चुनावों को बेहद गंभीरता से ले रही है। अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारकर पार्टी यह संकेत दे रही है कि आने वाले चुनावों में वह किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

मनरेगा का अंत, मोदी सरकार लाएगी नया 'विकसित भारत-जी राम जी' ग्रामीण रोजगार कानून, रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी और नए विकास मॉडल की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को अब पूरी तरह बदलते हुए एक नया कानून पेश किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025', जिसे संक्षेप में 'VB-G RAM G' के नाम से जाना जाएगा। यह बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और सोमवार को इसकी कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट भी की गई।

सरकार के मुताबिक नया कानून MGNREGA के अनुभव और पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत में हुए सामाजिक-आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बिल में स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब हर साल 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा, जबकि पहले यह संख्या 100 दिन थी। इसे ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने, गांवों में बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

सरकार ने बताया कि नए कानून में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण भारत में कौशल विकास और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे गांवों में काम करने वाले श्रमिकों को न केवल रोज़गार मिलेगा, बल्कि उनकी आय स्थिर होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार की संभावना बढ़ेगी।

हालांकि, इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला बेहद दुखद है। उनका आरोप है कि MGNREGA का नाम बदलना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक की विरासत को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने चेताया कि यदि यह बिल बिना व्यापक चर्चा के पास हुआ, तो इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस विरोध के बीच यह चर्चा भी हो रही है कि पहले 12 दिसंबर को कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था।

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण भारत में पिछले दो दशकों में तकनीकी बदलाव, कृषि उत्पादन की नई प्रणालियों और ग्रामीण श्रमिकों के बदलते आर्थिक स्वरूप ने पुराने कानून में सुधार की आवश्यकता पैदा कर दी थी। नए बिल में न केवल रोजगार के दिनों में वृद्धि की गई है, बल्कि ग्रामीण विकास को समग्र और रणनीतिक तरीके से मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार, आय और जीवन स्तर में सुधार मिले, जिससे भारत 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके।

सरकार का दावा है कि यह नया कानून सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत गांवों में जल संरक्षण, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता और अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस तरह ग्रामीण रोजगार और गांवों के समग्र विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से बढ़ावा मिलेगा।

इस तरह, MGNREGA का नया रूप 'विकसित भारत-जी राम जी' ग्रामीण रोजगार कानून न केवल रोजगार की गारंटी देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। आने वाले महीनों में संसद में इस बिल पर बहस और संभावित संशोधन तय करेंगे कि यह ग्रामीण भारत की वास्तविक जरूरतों और सामाजिक संतुलन के अनुरूप कितना कारगर साबित होता है।

देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी, 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' संसद में पेश, संयुक्त समिति को भेजने का फैसला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से ढालने और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्त तथा आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, 2025' विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्व-शासन वाले संस्थान के रूप में विकसित करना बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के निर्धारण और समन्वय को सरल बनाएगा, साथ ही शिक्षण, अध्ययन, शोध और नवाचार की गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक ले जाएगा।

विधेयक पेश करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक सक्षम, लचीली और परिणामोन्मुखी बनाने की जरूरत है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के गठन के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त कर पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता पर केंद्रित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे विश्वविद्यालयों को अकादमिक निर्णय लेने, शोध को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे भारत ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

हालांकि विधेयक के पेश होते ही सदन में इसका तीखा विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता पर चोट बताते हुए कहा कि यह विधेयक राज्य कानूनों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। उनका तर्क था कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है और इस तरह के प्रावधान संघीय ढांचे को कमजोर कर सकते हैं। आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, कांग्रेस की एस. जोतिमणि और द्रमुक के टी. वी. सेल्वागणपति ने भी विधेयक पर गंभीर आपत्तियां जताईं।

कुछ सांसदों ने आशंका व्यक्त की कि इसके जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है और राज्यों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों को लेकर यह आरोप भी लगाया गया कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदी थोपने और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा सकता है।

विपक्ष के तीखे विरोध और उठी शंकाओं के बीच सरकार ने भी लचीला रुख अपनाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदस्यों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना था कि समिति में सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और सदस्यों के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी दूर की जा सके।

इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा किसी राज्य की स्वायत्तता को कम करने या शिक्षा पर एकतरफा नियंत्रण स्थापित करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावी, स्वायत्त और पारदर्शी बनाना है, ताकि गुणवत्ता और मान्यता के उच्च मानक सुनिश्चित किए जा सकें। उनके अनुसार, यह विधेयक देश की शिक्षा प्रणाली को भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम सुधारात्मक कदम है।

कुल मिलाकर, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक ने संसद में व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे संघीय ढांचे और संस्थागत स्वायत्तता के लिए चुनौती मान रहा है। अब संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह विधेयक किस रूप में आगे बढ़ेगा और देश की शिक्षा प्रणाली को किस दिशा में ले जाएगा।

श्रेयस तलपडे और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से मिली सुप्रीम कोर्ट की राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता श्रेयस तलपडे और आलोक नाथ को एक संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों अभिनेताओं को जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

इस मामले में तलपडे के वकील ने अदालत में कहा कि अभिनेता को कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया गया था और इस कार्यक्रम से उन्होंने कभी कोई आर्थिक लाभ नहीं कमाया। वकील ने यह भी जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल किसी भी तरह की धोखाधड़ी या निवेशकों को बहकाने में शामिल नहीं थे।

सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत के आधार पर तलपडे और आलोक नाथ समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों अभिनेताओं ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्रचार किया, जिससे लोग निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ जांच करने का पूरा अधिकार है, लेकिन तलपडे और आलोक नाथ की गिरफ्तारी फिलहाल रोक दी जाए। इस राहत से दोनों अभिनेताओं को किसी भी गिरफ्तारी से पहले कानूनी सुरक्षा मिल गई है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा पर फिलहाल कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह मामला फिल्म और मीडिया उद्योग में ब्रांड प्रमोशन और वित्तीय निवेश के दावों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की संवेदनशीलता को उजागर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत की यह कार्रवाई जांच प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।

अनिल अंबानी समूह से जुड़े लेनदेन की परतें खुलीं, ईडी ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर से की लंबी पूछताछ

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को यस बैंक के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी राणा कपूर से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। यह पूछताछ ईडी के कार्यालय में हुई, जहां राणा कपूर के बयान मनी लान्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए। जांच एजेंसी का फोकस उस दौर पर है, जब राणा कपूर यस बैंक का नेतृत्व कर रहे थे और बैंक द्वारा अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऋण और निवेश प्रदान किए गए थे।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में कपूर और अंबानी समूह के बीच "क्विड प्रो क्वो" यानी किसी लाभ के बदले किसी अन्य लाभ के लेनदेन की आशंका है। जांच में यह सामने आया है कि 31 मार्च 2017 तक यस बैंक का अनिल अंबानी समूह के प्रति कुल एक्सपोजर करीब 6,000 करोड़ रुपये का था, जो महज एक साल के भीतर बढ़कर 31 मार्च 2018 तक लगभग 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एजेंसी इस तेज़ बढ़ोतरी के पीछे की परिस्थितियों, निर्णय प्रक्रिया और संभावित नियम उल्लंघन की गहन जांच कर रही है।

जांच के दायरे में खासतौर पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, जिनमें यस बैंक की ओर से बड़े निवेश और ऋण दिए गए थे। ईडी का आरोप है कि इन लेनदेन का एक बड़ा हिस्सा बाद में घाटे वाले निवेश यानी नॉन-परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो गया। अधिकारियों का दावा है कि इन सौदों के कारण यस बैंक को लगभग 3,300 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। गौरतलब है कि 68 वर्षीय राणा कपूर को यस बैंक में कथित रूप से अवैध तरीके से ऋण वितरण और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े अलग-अलग मनी लान्ड्रिंग मामलों में पहले भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। मौजूदा पूछताछ उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या अनिल अंबानी समूह को दिए गए ऋण और निवेश किसी आपसी समझौते या व्यक्तिगत लाभ से जुड़े थे।

ईडी सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेजों, बैंकिंग फैसलों और लेनदेन की समय-सीमा को लेकर सवाल किए गए हैं। एजेंसी इस मामले में सभी तथ्यों और सबूतों को जोड़कर यह तय करने की कोशिश कर रही है कि क्या बैंकिंग नियमों का उल्लंघन हुआ और क्या इसके पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका थी। आने वाले दिनों में इस मामले में जांच और तेज होने तथा नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

का उद्देश्य सनातन ग्रंथों में प्रार्थना की अवधारणा को समग्र दृष्टिकोण से समझना और इसके दार्शनिक, साहित्यिक तथा भक्ति आधारित पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करना था।

सम्मेलन का शुभारंभ संस्थान के सहायक निदेशक डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी ने किया। उन्होंने प्रार्थना की दार्शनिक प्रासंगिकता और समकालीन संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संस्थान के अध्यक्ष महामहोपाध्याय भद्रेशदास स्वामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि प्रार्थना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, मानसिक संतुलन और मोक्ष प्राप्ति का भी प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित विद्वानों और शोधार्थियों से अपील की कि वे प्रार्थना की बहुआयामी महत्ता को समझें और इसके अध्ययन को और गहन बनाएं। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों और भक्ति साहित्य पर आधारित अपने मौलिक शोध प्रस्तुत किए। इन शोधों में वेदों की स्तुति परंपरा, भक्ति साहित्य में शरणागति और अनन्य प्रेमभाव, प्रार्थना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इसके सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

संपादकीय

मां-बाप की सहमति तो न होगा विरोध

बदलते वक्त की धारा में युवाओं में बढ़ते प्रेम विवाह के रुझान को देखते हुए अब तक कठोर रही खापों ने भी रुख बदला है। जैसे कह रहे हों कि यदि मां-बाप राजी तो क्या करेगा काजी। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के गांव सोरम में देशभर की खाप पंचायतें तीन दिन तक जुटीं। जिसमें हरियाणा, पंजाब, उ.प्र., उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान आदि की विभिन्न जाति-धर्मों की 36 खाप बिरादरियों के प्रतिनिधि जुटे। रोचक यह है कि एक लाख से अधिक भागीदारों में आधे करीब 20-35 वर्ष के युवा थे। वजह यह भी थी कि खापों की सख्ती से बड़ी संख्या में युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। हालांकि, इस पंचायत में मौजूदा सामाजिक चुनौतियों मसलन इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याएं, दहेज, भ्रूण-हत्या, मृत्यु-भोज जैसी कुरीतियों पर व्यापक विमर्श हुआ, लेकिन प्रेम विवाह का मुद्दा मुखरता से छाया रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि सर्वखाप ने तय किया कि यदि माता-पिता की सहमति से प्रेम विवाह होता है तो खाप हस्तक्षेप नहीं करेगी। सर्वखाप पंचायत में देश की सबसे बड़ी बालियान खाप के प्रधान नरेश टिकैत का कहना था कि यहां इतने ज्यादा लोग इसलिए जुटे हैं कि मुद्दे कोई राजनीतिक या किसानों के न होकर, प्रेम-विवाह, अंतरजातीय विवाह शुरू करने, दहेज न लेने, मृत्युभोज बंद करने जैसे ज्वलंत विषयों से जुड़े रहे। आम राय रही है कि जिस विवाह को लेकर मां-बाप की सहमति होगी, उसमें समाज, रिश्तेदार अथवा खाप हस्तक्षेप नहीं करेगी।

दरअसल, खापों के रवैये में लचीलापन आने की एक बड़ी वजह यह रही है कि युवा तेजी से प्रेम विवाह की तरफ उन्मुख हैं। लेकिन जहां ऐसा करने में सख्ताई है वहां बड़ी संख्या में युवा कुंआरे बने हुए हैं। हरियाणा, उ.प्र व एनसीआर के कई गांवों में सैकड़ों की कुंआरों की फौज खड़ी हैं। अब यह सोच बन रही है कि प्रेम विवाहों से समाज की कई बुराइयां व मुश्किलें भी कम हो रही हैं। बदलते वक्त के साथ परंपरागत शादियों में अलगाव, तलाक व टकराव के मामले हालिया सालों में बढ़े हैं। कई नेताओं में इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई कि जिन जातियों में घड़ा व हुक्का-पानी एक है, उनमें शादियों की शुरुआत होनी चाहिए। समान कद वाली जातियों में भी शादी की बात छेड़ी गई, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बनी। साथ ही समान गोत्र की खेतिहर जातियों में भी विवाह पर विचार हुआ। कई लोग उदाहरण देते रहे कि जाटों के सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह ने अपनी तीन बेटियों व बेटे की अंतरजातीय शादी की। बताया जा रहा है कि जातीय अस्मिता और किसान संस्कृति की ध्वजवाहक जाट बिरादरी में विवाह से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीर मंथन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कई खापों के नेता इस बात को नकारते दिखे कि डीएनए मिक्सिंग से आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती हैं। तर्क दिया गया कि शरीर विज्ञान से जुड़ा कोई शोध-अनुसंधान इस बात की पुष्टि नहीं करता। बहरहाल, खापों की सकारात्मक सोच युवाओं के लिये नई उम्मीद लेकर आई है।

महान बनने के भ्रम में ओछी अमेरिकी हरकतें

> अभी जो खतरा भारतीय और बहुत से अन्य देशों के नागरिक एच वन वीजा को लेकर झेल रहे हैं, हो सकता है कि कल अमेरिका में कानून ही बदल दिया जाए। जो लोग वहां के नागरिक हैं उनसे भी वापस जाने को कहा जाए। ट्रंप ने आते ही उस कानून को बदला था, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाती थी।

जब से ट्रंप अमेरिका में सत्ता में दोबारा आए हैं, वे हर दिन कोई न कोई ऐसी घोषणा करते रहते हैं, जिससे दुनिया में हड़कम्प मच जाता है। उनका कहना है कि वह अमेरिका को दोबारा महान बनाना चाहते हैं, इसलिए हर काम वह करेंगे, जिससे अमेरिका के लोगों को फायदा हो। अपने संसाधनों का फायदा वे उठा सकें। इसलिए वे तरह-तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उनका लेबर डिपार्टमेंट एक्स पर लिख रहा है कि अमेरिका में नौकरियां अमेरिकी लोगों के लिए ही होनी चाहिए। यों इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि हर देश का नेता चाहता है कि उसके लोगों में बेरोजगारी घटे।

लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका ने जो तरक्की की है, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक जो परचम लहराया है, इसमें बाहरी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इनमें भारतीय सबसे अधिक हैं। थोड़े दिन पहले बिल गेट्स ने कहा था कि यदि हम भारतीय इंजीनियर्स को रोकेंगे, तो वे अपना गूगल बना लेंगे। अन्य बड़े कार्पोरेट्स भी ऐसा ही कह रहे हैं। पिछले दिनों एक पूर्व गुप्तचर अधिकारी ने कहा कि भारतीय लोगों के साथ अमेरिका में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। जिस सिलिकॉन वैली की दुहाई दी जाती है, उसे यहां तक पहुंचाने में हमारे देश के लोगों और प्रतिभाओं का भारी हाथ है।

अमेरिका ने दुनियाभर में एक ताकतवर देश की छवि बनाई है। डालर के मुकाबले दुनियाभर की अधिकांश मुद्राएं कमजोर मानी जाती हैं। युवा समझते हैं कि वे अपने सपनों को अमेरिका जाकर ही पूरा कर सकते हैं। कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि पूरे विश्व से दस करोड़ लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। यह अफसोस

की बात है कि युवा सिर्फ अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है।

लेकिन उन बातों को क्या कहिए जो हर रोज अमेरिका में हो रही हैं। जिन्हें इन्हीं युवाओं को झेलना है। पिछले दिनों ही दो खबरें आईं कि अब अमेरिका ने एच वन और एच फोर वीजा के तमाम आवेदनों को रोक दिया है। इसके अलावा बहुत से देशों के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि आवेदनकर्ताओं के पहले वे सोशल मीडिया अकाउंट्स चैक करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि कोई अमेरिका विरोधी तो यहां नहीं आना चाहता। एच वन वीजा को वर्क वीजा कहा जाता है। इसी के आधार पर आप वहां काम कर सकते हैं। इसे पाना युवाओं की सबसे बड़ी इच्छा होती है। इसके अलावा एच फोर वीजा पति या पत्नी के लिए होता है। इसके होने पर आप वहां काम नहीं कर सकते। इसे मौलिक अधिकार की तरह अब तक देखा जाता रहा है, लेकिन जैसे अब इस सोच के दिन लद गए हैं। यही नहीं, उन्होंने बारह देश के नागरिकों पर अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये देश हैं— अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गुएना, एरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। इससे पहले भी बहुत से देशों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस भारत से मैत्री की कसमें ट्रंप लगातार खाते रहे हैं, उनके निशाने पर सबसे अधिक भारतीय ही हैं। ट्रंप को लड़ना आतंकवाद से था, लेकिन वे भारतीयों से लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में यहां के लोगों ने अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। जबकि देखा जाए, तो वहां भारतीय कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। उन्हें वेतन भी कम मिलता है। उन्हें छिपे हुए नस्लवाद का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब यह नस्लवाद छिपा हुआ नहीं रहा। खुलेआम व्हाइट सुप्रीमेसी की बात की जा रही है। हालांकि, ट्रंप की जीत में ग्रामीण अमेरिका के गोरों के साथ-साथ, वहां के उन नागरिकों का भी हाथ रहा है, जिनकी जड़ें भारत में हैं। भारतीयों के बारे में वहां मशहूर रहा है कि ये लोग शांतिप्रिय होते हैं। अपने काम से काम रखते हैं। अपने काम को अच्छी तरह से करना जानते हैं। जबकि अमेरिका के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे न तो पढ़ना-लिखना चाहते हैं, न ही किसी विशेष योग्यता को प्राप्त करने में उनकी दिलचस्पी है। इसी कारण वहां अन्य देश के लोग काम करने जाते हैं। और वहां के बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य कम्पनियों को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं।

लेकिन एच वन पर रोक लगाकर रास्तों को रोका जा रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा कि एच वन बी जैसी एब्यूज (गाली) को बंद होना चाहिए। बहुत से अन्य रिपब्लिकन्स भी ऐसा ही कह रहे हैं। जब सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोग खुलेआम किसी देश के लोगों पर निशाना साधने लगें, तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों का क्या होता होगा। अमेरिका में दिवाली पर सरकारों की तरफ से भारतीयों को बधाई दी जाती रही है। लेकिन इस बार दिवाली के आसपास वहां के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी हिन्दू पत्नी उषा वेंस भी ईसाई विश्वासों को मानें और ईसाई धर्म अपना लें। उन्होंने दिवाली की बधाई भी किसी को नहीं दी। वहां इन दिनों भारतीयों को लगातार तरह-तरह के कटाक्ष झेलने पड़ रहे हैं। लोग उन्हें रास्ते में रोककर पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। उनसे मार-पीट कर रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि अपने देश वापस जाओ। बल्कि कई साल पहले पोलैंड में एक भारतीय घूम रहा था। वहां उसे रोककर एक अमेरिकी ने कहा कि तुम यहां भी आ पहुंचे। कम्पनियों से कहा जा रहा है कि वे भारतीय लोगों को नौकरी न दें। अगर देंगी, तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, नहीं दी जाएंगी। अमेरिका के वे विश्वविद्यालय जो विदेशी बच्चों की दी गई मोटी फीस से चलते हैं, वहां भारतीय छात्रों की संख्या घट रही है, क्योंकि कौन ऐसे देश में जाना चाहेगा , जहां जीवन की खैर नहीं। और तो और वहां स्कूलों में भी इस तरह का नस्लवाद पैर पसार रहा है। बच्चों को तरह-तरह से तंग किया जा रहा है। अभी जो खतरा भारतीय और बहुत से अन्य देशों के नागरिक एच वन वीजा को लेकर झेल रहे हैं, हो सकता है कि कल अमेरिका में कानून ही बदल दिया जाए। जो लोग वहां के नागरिक हैं उनसे भी वापस जाने को कहा जाए। ट्रंप ने आते ही उस कानून को बदला था, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाती थी। हालांकि, अदालत ने इसके खिलाफ फैसला दिया। अमेरिका में पचपन लाख के करीब भारतीय रहते हैं। यह एक बड़ी आबादी है। लेकिन कोई देश अगर तय ही कर ले, तो खदेड़ने में वक्त नहीं लगता। इस प्रसंग में युगांडा के ईदी अमीन की याद आती है। सत्तर के दशक में उन्होंने भी लम्बे समय से वहां रहने वाले लोगों को खदेड़ा था। दरअसल, सरकारों के पास जब अपने लोगों को वास्तविकता में देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे एक कम्युनिटी के खिलाफ, दूसरी को भड़काती हैं। यही अमेरिका में हो रहा है।

प्रेरणा

जहां से अध्यात्म आरंभ होता है और लक्ष्य स्वयं बन जाता है

अध्यात्म का वास्तविक लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह ईश्वर, ब्रह्म या सत्य को भी केवल शब्दों और कल्पनाओं में ही खोजता रहता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि आत्मसाक्षात्कार ही साधना का मूल मार्ग है और वही अध्यात्म की पूर्णता का द्वार खोलता है। आत्मसाक्षात्कार कोई रहस्यमय या चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। यही वह बिंदु है जहां साधना कर्मकांड से ऊपर उठकर चेतना का विज्ञान बन जाती है। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है कि प्रत्येक जीव में जो चेतना विद्यमान है, वही आत्मतत्व है। ऋषि वशिष्ठ ने जीव की चेतना को ही आत्मा कहकर परिभाषित किया है। यह आत्मा न किसी काल से बंधी है, न किसी परिस्थिति से। यह वही तत्व है, जिसके चारों ओर समस्त धर्मों, दर्शनों और साधनाओं की संरचना हुई है। सनातन परंपरा में आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और आत्मबोध को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋषि, महर्षि, साधु, संत और परमहंस—सभी की साधना का केंद्र यही आत्मतत्व रहा है। उनके उपदेशों, वचनों और अनुभवों में बार-बार आत्मप्रकाश की चर्चा मिलती है।

आत्मप्रकाश को लेकर साधकों के मन में अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा साधना के द्वारा प्रकाशित होती है या आत्मा पहले से ही प्रकाशित है। यदि आत्मा हर जीव में विद्यमान है, तो फिर वह अप्रकाशित कैसे हो सकती है। क्या प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अलग-अलग है और क्या उसका स्वरूप भी भिन्न है। ऐसे प्रश्न साधक को उलझा सकते हैं, किंतु शास्त्र इन्हें भ्रम मानते हैं। आत्मा न तो कम प्रकाशित होती है और न अधिक, वह तो सदा स्वयंप्रकाश है। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य की दृष्टि उस प्रकाश की ओर मुड़ी है या नहीं।

इसी संदर्भ में आत्मसाक्षात्कार शब्द भी भ्रम उत्पन्न करता है। जब आत्मा पहले से ही हमारे भीतर साक्षात विद्यमान है, तो फिर उसके साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों। वास्तव में आत्मसाक्षात्कार का अर्थ आत्मा को उत्पन्न करना नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानना है। यह पहचान मन, बुद्धि और अहंकार के आवरण हटने पर होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ऋषि-मुनि इस विषय पर गहन चिंतन करते आए हैं और आज भी साधक इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

आत्मा शाश्वत है, किंतु अमूर्त है। उसका अनुभव सहज नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा जीवन मन और बुद्धि के स्तर पर संचालित होता है। हम जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वे मन और बुद्धि की क्रियाएं हैं। आत्मा इनसे परे साक्षी रूप में स्थित रहती है। शास्त्र कहते हैं कि जीवन में घटने वाली घटनाओं का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि घटनाएं कर्म और काल के अधीन होती हैं, जबकि आत्मा कालजयी है। सुख और दुख भी आत्मा को नहीं छूते, वे केवल मन की अनुभूतियां हैं। शरीर को गर्मी और ठंडक का अनुभव होता है, इंद्रियां स्वाद और रूप को ग्रहण करती हैं, मन अच्छा-बुरा तय करता है। हित और अहित की यह परिभाषा भी स्थायी नहीं होती। जो आज सुख देता है, वही कल बोझ बन जाता है। मन किसी वस्तु या स्थिति को पाने में सुख अनुभव करता है और प्राप्ति के बाद उसी से ऊब जाता है। यह चक्र बार-बार चलता रहता है। यह सब आत्मा की अनुभूति नहीं है, क्योंकि आत्मा इससे कहीं अधिक गहन, स्थिर और व्यापक है।

आत्मा की अपनी एक यात्रा है, जो शरीर की यात्रा से भिन्न है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और नष्ट हो जाता है। मन बदलता रहता है, बुद्धि विकसित होती है, लेकिन आत्मा इन सबकी साक्षी बनी रहती है। जब व्यक्ति की दृष्टि बदलती है, तो उसका दर्शन बदल जाता है और दर्शन बदलते ही जीवन की पूरी संरचना बदल जाती है। व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म की शुद्धि का बोध बहुत कम लोगों को होता है। यहीं से धर्म और अध्यात्म का वास्तविक प्रश्न उठता है। शास्त्र कहते हैं—'शरीर खलु धर्म साधनम्', अर्थात शरीर ही धर्म का साधन है। धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ या अनुष्ठान नहीं, बल्कि वह मूल स्वभाव है, जिसके अनुसार कोई तत्व कार्य करता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है। वह किसी भेदभाव के बिना अपना धर्म निभाती है। उसी प्रकार मनुष्य का भी एक मूल धर्म है और आत्मा का भी अपना धर्म है। आत्मा अपने धर्म का निर्वाह बिना किसी विवेक या स्वार्थ के करती है। उस धर्म को जानना और समझना ही जीवन का प्रथम लक्ष्य है।

अक्सर लोग पूजा-पद्धतियों और धार्मिक पहचान को ही धर्म मान लेते हैं, जबकि वास्तविक धर्म वह है, जो आत्मा के स्तर पर स्वतः घटित होता है। आत्मा जो करती है, वही उसका धर्म है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यदि यह सत्य है, तो फिर हमारी यात्रा केवल इस एक जन्म की नहीं हो सकती। हम शरीर से नए हैं, लेकिन आत्मा से अत्यंत प्राचीन हैं।

ऐसे में आत्मसाक्षात्कार का अर्थ आत्मा को पाना नहीं, बल्कि आत्मा की उस निरंतर यात्रा को जानना है, जिसे वह युगों से तय करती आ रही है। आत्मा की यात्रा सतत है, उसके अनेक पड़ाव हैं, जो बार-बार लौटकर आते हैं। जब साधक को आत्मतत्व का बोध होता है, तो पूरा मार्ग सहज हो जाता है। इसी अवस्था में ऋषि त्रिकालदर्शी कहे गए, क्योंकि वे आत्मा की यात्रा को समय के पार देख पा रहे थे।

यही कारण है कि आत्मा को ब्रह्मस्वरूप कहा गया—'अहम् ब्रह्मास्मि'। यह कोई अहंकार का वाक्य नहीं, बल्कि आत्मबोध का उद्घोष है। जब आत्मसाक्षात्कार होता है, तब अध्यात्म कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। यहीं साधना पूर्ण होती है और यहीं से वास्तविक मुक्ति का आरंभ होता है।

भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे, समझिए सियासी मायने

समकालीन भाजपा के कुशल सियासी शिल्पी समझे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का चाणक्य करार दिए जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की युगल प्रभावशाली जोड़ी ने 14 दिसंबर को यकायक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तीसरी पीढ़ी के कद्दावर और सूझबूझ वाले युवा नेता नितिन नबीन के नाम की घोषणा करवाकर न केवल सबको चौंकाया है, बल्कि एक तीर से कई सियासी निशाने भी साधे हैं। इसके सियासी मायने भी दूरगामी और दिलचस्प साबित होंगे, क्योंकि मोदी-शाह के सियासी तरकश से निकले इस प्रभावी तीर ने आरएसएस-भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी आश्चर्य चकित कर दिया है। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सत्तारूढ़ राजग के नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को गत दिनोंतत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी पशोपेश में पड़कर चौंक गए हैं और इस अप्रत्याशित निर्णय को सराहा, क्योंकि यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल की समाप्ति और उनको मिले बार-बार कार्य विस्तार की अवधि के दौरान आई है, जो नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव तक संगठन की कमान संभालेंगे। हालांकि, इस बात की सुगबुगाहट लंबे अरसे से जारी थी और बड़े-बड़े नाम इस होड़ में शामिल थे। इसलिए नितिन नबीन की नियुक्ति से मोदी-शाह का सियासी पलड़ा पुनः भारी प्रतीत हुआ है।

जहां तक इस नियुक्ति के कारण की बात है तो पार्टी ने नितिन नबीन के संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़, प्रशासनिक क्षमता और सिक्किम/छत्तीसगढ़ में प्रभारी/सह-प्रभारी के रूप में उनकी उल्लेखनीय सफलता को आधार बनाया है। बताया जाता है कि पांच बार विधायक और तीन बार मंत्री रह चुके नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, पटना पश्चिम इलाके से हैं तथा बूथ स्तर प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी इस नई नियुक्ति का बिहार सहित पूर्वी भारत की सियासत पर भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

देखा जाए तो भाजपा आलाकमान का यह कदम बिहार में भाजपा की मजबूती को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है, जहां नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं जो पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक है। वहीं, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्हें दिल्ली में आधिकारिक आवास और केंद्रीय मंत्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल पार्टी उनके मनोनयन की राष्ट्रीय रणनीति से सुपरिचित है जोकि जेनरेशन नेक्स्ट को बढ़ावा देती है तथा बंगाल चुनाव जैसी चुनौतियों के लिए समय रहते ही तैयार करती है। यह पीएम मोदी और एचएम अमित शाह की प्रभावशाली सियासी दिशा में एक नई निरंतरता का संकेत है, जिसमें युवा नेतृत्व से नई ऊर्जा की उम्मीद है। पार्टी मामलों के जानकार बताते हैं कि नितिन नबीन की नई नियुक्ति बिहार की राजनीति में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और कायस्थ वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत देती है। यह कदम बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व दिलाता है, जहां नबीन की जमीनी पकड़ और बांकीपुर सीट पर लगातार जीत भाजपा के लिए मॉडल बनी हुई है। जहां तक भाजपा की मजबूती की बात है तो इस नियुक्ति से बिहार में भाजपा का कैडर प्रबंधन और चुनावी रणनीति तेज होगी, खासकर नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहते हुए। यही नहीं, भारत का सर्वाधिक प्रबुद्ध और प्रशासनिक प्रभाव रखने वाला कायस्थ समुदाय, जो भाजपा का कोर वोटर है, इससे प्रेरित होगा तथा पार्टी का शहरी आधार पटना जैसे इलाकों में और सशक्त बनेगा।

जहां तक एनडीए पर प्रभाव की बात है तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भाजपा की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि नबीन का राष्ट्रीय पद बिहार में केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी बढ़ाएगा। साथ ही युवा नेतृत्व का उदाहरण स्थापित कर अन्य दलों को चुनौती मिलेगी, विशेषकर आगामी विधानसभा चुनावों में। वहीं, संभावित चुनौतियां यह हैं कि मंत्री पद के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी से बिहार फोकस कम न हो, यह चिंता बनी रहेगी, हालांकि उनका छत्तीसगढ़ प्रभारी वाला अनुभव आश्वासन देता है। विपक्षी दल इसे भाजपा की बिहार-केंद्रित रणनीति के रूप में देखकर जवाबी हमला बोल सकते हैं।

नितिन नबीन भाजपा की नई रणनीति में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने, संगठनात्मक मजबूती और पूर्वी भारत में विस्तार के प्रमुख स्तंभ बनेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे बूथ स्तर प्रबंधन, चुनावी तालमेल और राज्य इकाइयों के बीच समन्वय संभालेंगे। इससे पार्टी में युवा जुड़ाव बढ़ेगा। नबीन की नियुक्ति से भाजपा 2029 लोकसभा चुनावों के लिए नेक्स्ट जेन लीडरशिप तैयार करेगी, जहां युवाओं से कनेक्ट करना प्राथमिकता होगी। वहीं,, छत्तीसगढ़ प्रभारी के अनुभव से बूथ मजबूती का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा।

जहां तक चुनावी रणनीति की बात है तो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और असम विधानसभा चुनावों में नितिन नबीन संगठन विस्तार व तालमेल प्रबंधन करेंगे, और बिहार में मिली हालिया सफलता को दोहराने का लक्ष्य रखेंगे। इससे पूर्वी भारत पर फोकस से पार्टी का क्षेत्रीय आधार सशक्त बनेगा। जहां तक संगठनात्मक भूमिका की बात है तो जेपी नड्डा के बाद वे केंद्रीय नेतृत्व व राज्य नेताओं के बीच पुल का काम करेंगे, और पीएम मोदी की दृष्टि को जमीन पर उतारेंगे। वहीं कायस्थ (पश्चिम बंगाल में राढ़ी कायस्थ) जैसे कोर वोट बैंक को साधते हुए सामाजिक समीकरण मजबूत होंगे।

नितिन नबीन की प्रमुख प्राथमिकताएँ भाजपा के संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रियता बढ़ाना और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना रहेंगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण शामिल हैं। वहीं संगठनात्मक मजबूती के लिए वे बूथ प्रबंधन मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे, जैसा छत्तीसगढ़ में सफल रहा, तथा राज्य इकाइयों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कायस्थ जैसे कोर वोट बैंक को साधते हुए शहरी और प्रबुद्ध मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाना लक्ष्य होगा।

अभियान

केदार की घाटियों से उठती शिव चेतना

हिमालय की विराट और शांत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित केदारनाथ धाम वह पावन स्थल है, जहां पहुंचकर मनुष्य अपने अस्तित्व को ईश्वर की विराट सत्ता में विलीन होता हुआ अनुभव करता है। यह धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन धर्म की उस अमर धारा का प्रतीक है, जो युगों से मानव को तप, त्याग और आत्मबोध का मार्ग दिखाती आई है। बाबा केदार का यह धाम चारधाम यात्रा का वह पड़ाव है, जहां पहुंचने के लिए शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा होती है। कठिन रास्ते, ऊंची चोटियां और बदलता मौसम मानो श्रद्धालु से पूछते हैं कि वह किस भाव से यहां आया है।

जब वर्ष के अंतिम महीनों में हिमालय पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, तब केदारनाथ धाम धीरे-धीरे मौन में चला जाता है। शीतकाल में भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट विधिपूर्वक बंद कर दिए जाते हैं। यह क्षण भक्तों के लिए अत्यंत भावुक होता है, क्योंकि मानो बाबा केदार स्वयं अपने भक्तों से कुछ समय के लिए विदा ले रहे हों। इसके बाद भगवान

केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली को वैदिक मंत्रों और शंखनाद के साथ उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहां पूरे शीतकाल बाबा की पूजा-अर्चना निरंतर चलती रहती है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर कभी अनुपस्थित नहीं होता, केवल स्थान बदलता है। जैसे ही बसंत ऋतु हिमालय की घाटियों में जीवन का संचार करती है, वैसे ही भक्तों के हृदय में बाबा केदार के दर्शन की उत्कंठा जाग उठती है। बर्फ पिघलने लगती है, पहाड़ी रास्ते खुलने लगते हैं और आस्था फिर से केदारनाथ की ओर बढ़ने लगती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि कोई साधारण घोषणा नहीं होती। यह निर्णय वैदिक पंचांग, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर लिया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा के बाद यह तिथि घोषित की जाती है। सनातन परंपरा में अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसी कारण बाबा केदार के कपाट भी इसी पवित्र तिथि को खोले जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की संभावना जताई जा रही है। जिस क्षण मंदिर के द्वार खुलते हैं, वह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावनाओं का महासागर बन जाता है। हर-हर महादेव के जयघोष, शंखों की ध्वनि और मंत्रोच्चार से पूरा हिमालय गूंज उठता है।

कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में प्रतिदिन बाबा केदार की दिव्य आराधना होती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती में भगवान शिव का अभिषेक, श्रृंगार और भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे शिवलोक तक पहुंचती है और भक्तों के जीवन के कष्ट हर लिए जाते हैं। सायंकाल जब दीपों की ज्योति मंदिर प्रांगण को आलोकित करती है और मंत्रों की गूंज घाटियों में फैलती है, तब धाम का वातावरण अलौकिक हो उठता है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर बाबा के दर्शन करते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं।

केदारनाथ की यात्रा केवल भौगोलिक दूरी तय करना नहीं, बल्कि यह आत्मा के भीतर की यात्रा मानी जाती है। दुर्गम रास्ते, ऊंचाई और मौसम की अनिश्चितता श्रद्धालु के धैर्य, संयम और विश्वास की परीक्षा लेती है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त कुछ न कुछ पीछे छोड़कर आता है और कुछ नया लेकर लौटता है। यही कारण है कि केदारनाथ से लौटने के बाद व्यक्ति के दृष्टिकोण और जीवन में एक गहरा परिवर्तन देखने को मिलता है।

ऐसी मान्यता है कि बाबा केदार के दर्शन से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जीवन को नई दिशा मिलती है। वर्ष 2026 में जैसे ही कपाट खुलेंगे, हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य धाम एक बार फिर भक्तों को अपनी ओर बुलाएगा। वहां हर कदम पर आस्था की गूंज होगी, हर श्वास में शिव का स्मरण होगा और हर हृदय बाबा केदार की करुणा और कृपा से भर उठेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

पश्चिम रेलवे द्वारा मानव तस्करी विरोधी,क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा 15 दिसंबर, 2025 को मानव तस्करी विरोधी विषय पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, बचाव, पुनर्वास तथा उन्हें उनके परिवारों से पुनर्मिलन सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। यह पहल रेलवे परिसरों को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील एवं मानवीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन रेलवे सुरक्षा बल (RPF), पश्चिम रेलवे द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षा श्रीमती विजया किशोर रहाटकर; पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता; मुंबई पुलिस की उपायुक्त श्रीमती रागसुधा आर. (IPS); वरिष्ठ सलाहकार श्रीमती निशिता दुबे; रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक-सह-प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सदानी; पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह सहित पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा विशिष्ट संसाधन व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर मानव तस्करी की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना तथा त्वरित एवं संवेदनशील प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना था। कार्यशाला में दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सत्र-1 का विषय "मानव तस्करी के आयाम, कानून एवं प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका" था, जबकि सत्र-2 "मानव तस्करी नेटवर्क को बाधित करने हेतु इंटर-सेक्टोरल कन्वर्जेंस को सुदृढ़ करना" विषय पर केंद्रित था। दोनों सत्रों के उपरांत संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया किशोर रहाटकर ने अपने संबोधन में रेलवे परिसरों में मानव तस्करी की रोकथाम एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारतीय रेल, जिसमें पश्चिम रेलवे भी शामिल है, की "मेरी सहेली" पहल की विशेष रूप से प्रशंसा की। यह एक समर्पित सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत महिला रेलवे सुरक्षा बल (RPF) टीमें अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों को सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें महिला यात्रियों में विश्वास एवं आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं तथा रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, समावेशी एवं महिला-अनुकूल बनाती हैं।

श्रीमती रहाटकर ने आगे रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सहायकों (कुलियों), हाउसकीपिंग स्टाफ एवं अन्य फ्रंटलाइन ग्राउंड स्टाफ के नियमित प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि चौबीसों घंटे कार्यरत ये कर्मचारी प्रायः यात्रियों के प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं और खोए हुए, घर से भागे हुए अथवा सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की शीघ्र पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं प्रतिक्रिया तंत्र और अधिक मजबूत हो सकता है।

सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज से सीधे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक तंत्र है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी का अभिन्न अंग है, जिसके लिए सतर्कता, संवेदनशीलता तथा सशक्त मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन आवश्यक है।

कार्यशाला के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा "नन्हे फरिश्ते" एवं "ऑपरेशन डिग्निटी" अभियानों के अंतर्गत किए गए प्रयासों की जानकारी भी साझा की गई। पिछले दो वर्षों में कुल 1,573 बच्चों—जिसमें वर्ष 2024 के दौरान 842 बच्चे तथा वर्ष 2025 (अब तक) 731 बच्चे शामिल हैं—को असुरक्षित परिस्थितियों से बचाकर पुनर्वासित किया गया तथा उनके परिवारों से पुनर्मिलन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन संबंधित राज्य सरकारों एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारियों के सहयोग से प्रभावी रूप से किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल एवं राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मानव तस्करी की रोकथाम तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता एवं इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा उभरती प्रतिभाओं का सम्मान एवं स्वच्छता सशक्तिकरण पहल का शुभारंभ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा मुंबई स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में निबंध, चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर "स्वच्छता से सशक्तिकरण की शुरुआत" शीर्षक से एक सामाजिक कल्याण पहल का भी शुभारंभ किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निबंध, चित्रकला एवं पेंटिंग तथा अंतर-मंडलीय चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता की तीन श्रेणियों में कुल 37 बाल विजेताओं को पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती नीता गुप्ता द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। श्रीमती नीता गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शौक अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की रचनात्मकता एवं प्रदर्शन की सराहना की। इसी कार्यक्रम के दौरान "स्वच्छता से सशक्तिकरण की शुरुआत" परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। इस पहल के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं गरिमा को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल के तहत पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को श्रीमती नीता गुप्ता द्वारा सैनिटरी नैपकिन, तौलिया एवं साबुन सहित स्वच्छता किट प्रदान की गई, जिससे महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के प्रति पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया गया।

पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा समाज के कल्याण हेतु समावेशी सामाजिक पहलों को निरंतर समर्थन करती रही है।

श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देशन में 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) की पहल

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जीपीआई की समीक्षा बैठक

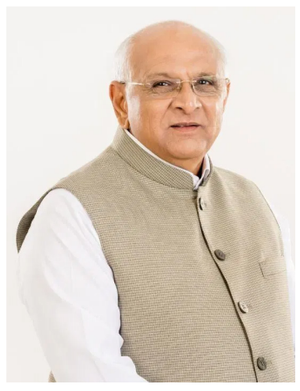

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरकार के विभिन्न विभाग राज्य के नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नागरिक केंद्रित योजनाओं, सेवाओं, विकासोन्मुखी कार्यों, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तथा शिकायत निवारण के कामकाज से करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में इस उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अलग अलग प्रकार के कामकाज के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को 'सीएम डैशबोर्ड' पर एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाया गया है।

देश में सुशासन के रोल मॉडल के रूप में स्थापित गुजरात में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का दृष्टिकोण सुनिश्चित हो तथा योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह 'सीएम डैशबोर्ड' कार्यरत किया गया है।

टेक्नोलॉजी के समुचित उपयोग की पहलरूपी में यह 'सीएम डैशबोर्ड' देश के अन्य राज्यों के लिए जन हितोन्मुखी व योजनागत कार्यों के मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन के लिए एक उदाहरणरूपी प्लेटफॉर्म बना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुड गवर्नेंस की इस उज्ज्वल परंपरा को गतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से समग्रोन्मुखी गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) तैयार करवाया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस जीपीआई के संदर्भ में गांधीनगर में विभागों की कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री श्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड, सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष श्री मुकेश पुरी, कृषि, ऊर्जा, नर्मदा जल संसाधन विभागों के अपर मुख्य सचिव, आदिजाति, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया तथा अन्य संबंधित विभागों के सचिव भी सहभागी हुए।

भावनगर रेलवे मंडल पर आयोजित 68वीं पेंशन अदालत में पेंशन संबंधी 225 मामलों का हुआ निपटारा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर दिनांक 15 दिसंबर, 2025 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में "68वीं पेंशन अदालत" का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत में मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। पेंशन भुगतान आदेश (PPO), फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स, ग्रुप इंस्योरेंस सहित पेंशन से जुड़े ब्रॉडगेज वर्कशॉप के 8 मामले और मंडल कार्यालय के 217 मामलों सहित कुल 225 मामलों का तत्परता एवं संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पेंशन अदालत को सफल बनाने में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, निपटारा शाखा एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके समन्वित प्रयासों से सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सका।

पेंशन से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान एवं त्वरित कार्यवाही के लिए "ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन" तथा "अखिल भारतीय रेलवे पेंशनर्स कल्याण महासंघ (All India Railway Pensioners Welfare Federation)" द्वारा प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर श्री हिमाँशु शर्मा (अपर मंडल रेल प्रबंधक), श्री हुबलाल जगन (वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी), श्री मोहित पांचाल (वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक), श्री वाई. राधेश्याम (सहायक कार्मिक अधिकारी), श्री संतोष कुमार वर्मा (सहायक कार्मिक अधिकारी), श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह (वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी – ब्रॉडगेज वर्कशॉप) एवं श्री संजय सक्सेना (सहायक मंडल वित्त प्रबंधक) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सोना वायदा नए सुनहरे शिखर पर पहुँचा: चांदी वायदा में 5280 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 15 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 33744.32 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 139977.29 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 29083.35 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32905 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 173728.49 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 33744.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 139977.29 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32905 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2042.62 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 29083.35 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 134204 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 135496 रुपये के ऑल टाइम हाई स्तर पर और नीचे में 134204 रुपये पर पहुंचकर, 133622 रुपये के पिछले बंद के सामने 1548 रुपये या 1.16 फीसदी की तेजी के संग 135170 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 1339 रुपये या 1.26 फीसदी की तेजी के संग 107771 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 174 रुपये या 1.31 फीसदी की तेजी के संग 13499 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 131500 रुपये के भाव पर खूलकर, 133590 रुपये के दिन के उच्च और 131500 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1655 रुपये या 1.26 फीसदी की तेजी के संग 133300 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132729 रुपये के भाव पर खूलकर, 133859 रुपये के दिन के उच्च और 132492 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 131895 रुपये के पिछले बंद के सामने 1650 रुपये या 1.25 फीसदी की तेजी के संग 133545 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 194747 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 199046 रुपये और नीचे में 194681 रुपये पर पहुंचकर, 192851 रुपये के पिछले बंद के सामने 5280 रुपये या 2.74 फीसदी बढ़कर 198131 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 5132 रुपये या 2.65 फीसदी की तेजी के संग 198675 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 5207 रुपये या 2.69 फीसदी की मजबूती के साथ 198700 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 2847.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 13.1 रुपये या 1.19 फीसदी बढ़कर 1109.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.3 रुपये या 0.41 फीसदी गिरकर 315.4 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.4 रुपये या 0.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 281.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 45 पैसे या 0.25 फीसदी टूटकर 181.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1804.89 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5229 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5247 रुपये और नीचे में 5206 रुपये पर पहुंचकर, 15 रुपये या 0.29 फीसदी घटकर 5213 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 15 रुपये या 0.29 फीसदी गिरकर 5213 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 380.4 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 384 रुपये और नीचे में 374.3 रुपये पर पहुंचकर, 376.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 1 रुपये या 0.27 फीसदी घटकर 375.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 60 पैसे या 0.16 फीसदी टूटकर 375.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 933.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 6.7 रुपये या 0.72 फीसदी की बढ़त के साथ 934.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 15944.64 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 13138.71 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2129.99 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 193.78 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 16.52 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 506.81 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 386.81 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1408.93 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15541 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 71186 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 18507 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 286547 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 30681 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16470 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39780 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 115635 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19032 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40525 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 32696 पॉइंट पर खूलकर, 32971 के उच्च और 32526 के नीचले स्तर को छूकर, 755 पॉइंट बढ़कर 32905 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 13.8 रुपये की गिरावट के साथ 33.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 55 पैसे की नरमी के साथ 15.7 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 137000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 638 रुपये की बढ़त के साथ 1723 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2251.5 रुपये की बढ़त के साथ 5550 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1110 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.8 रुपये की बढ़त के साथ 16.83 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.15 रुपये की गिरावट के साथ 2.61 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 2.7 रुपये की गिरावट के साथ 42.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 10 पैसे की नरमी के साथ 19.75 रुपये हुआ।

इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 475.5 रुपये की गिरावट के साथ 1059.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.68 रुपये की गिरावट के साथ 12.37 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.12 रुपये की गिरावट के साथ 3.01 रुपये हुआ।

फियो ने भारत के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी का स्वागत किया, नवंबर में व्यापार घाटे में तेज गिरावट: फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2025। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम व्यापार आंकड़ों पर टिपण्णी करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने भारत के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी पर संतोष जताया जो देश के निर्यात सेक्टर की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है।

भारत का वस्तु व्यापार नवंबर में 38.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया जो 19.37 प्रतिशत की मजबूत वर्ष दर वर्ष वृद्धि को प्रदर्शित करता है। महीने के दौरान वस्तु आयात 62.66 बिलियन डॉलर का रहा। सेवा सेक्टर के मोर्चे पर निर्यात में उल्लेखनीय बढोतरी हुई जो 32.11 बिलियन डॉलर से बढ़कर 35.86 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सेवा आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.25 बिलियन डॉलर की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 17.96 बिलियन डॉलर हो गया।

श्री एस सी रल्हन ने कहा कि सेवा निर्यात में मजबूत गति के साथ वस्तु निर्यात में लगभग 19.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि भारत के निर्यात सेक्टर के लिए बहुत आशाजनक संकेत है। व्यापार में तेज गिरावट लगातार जारी भूराजनीतिक तनाव और दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी वैश्विक मांग को दक्षतापूर्वक पूरा करने में भारतीय निर्यातकों की क्षमता को रेखांकित करती है।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर, भारत का कुल निर्यात नवंबर में 73.99 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 64.05 बिलियन डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। महीने के दौरान कुल आयात में मामूली गिरावट आई जो जो नवंबर 2024 के 81.11 बिलियन डॉलर की तुलना में घटकर 80.63 बिलियन डॉलर पर आ गया। एक मुख्य सकारात्मक विशेषता वस्तु व्यापार घाटे में आई कमी रही जो अक्तूबर के 41.68 बिलियन डॉलर से कम होकर 24.53 बिलियन डॉलर पर आ गया। यह मजबूत निर्यात गति और बेहतर व्यापार प्रबंधन को प्रदर्शित करता है।

श्री रल्हन ने इस बात पर भी बल दिया कि कई प्रमुख सेक्टरों में निरंतर गतिशीलता के साथ साथ निर्यात बाजारों के विविधीकरण ने निर्यात वृद्धि को सहायता देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतिगत सहायता, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और प्रतिस्पर्धी निर्यात वित्तपोषण के साथ, भारत का निर्यात आगे आने वाले महीनों में इस सकारात्मक मार्ग को बनाये रखने की अच्छी स्थिति में है।

फिये प्रमुख ने दुहराया कि अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 50 प्रतिशत का उच्च टैरिफ थोपे जाने के बावजूद अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा। यह स्पष्ट रूप से भारत के निर्यातक समुदाय की गतिशीलता और अनुकूलता प्रदर्शित करता है। इस अवधि के अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्यों में यूएई, नीदरलैंड, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्ला देश, सऊदी अरब और हांगकांग शामिल थे। आयात के मामले में प्रमुख आयातक देशों में चीन, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और जापान शामिल थे। श्री रल्हन ने दुहराया कि लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने, अनुपालन तथा प्रक्रियागत चुनौतियों को सरल बनाने और निर्यात वृद्धि को बनाये रखने तथा व्यापार घाटे में और कमी लाने के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

निवेशकों का भरोसा दिखा, ICICI प्रूडेंशियल AMC के आईपीओ को दूसरे दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शुमार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बाजार से मजबूत प्रतिक्रिया मिल रही है। आईपीओ के दूसरे दिन तक निवेशकों की दिलचस्पी साफ नजर आई, जिसके चलते यह इश्यू कुल 2.11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। खासतौर पर गैर-संस्थागत निवेशकों और योग्य संस्थागत खरीदारों की ओर से भारी मांग दर्ज की गई है, जिससे बाजार में इस निर्गम को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कुल 3 करोड़ 50 लाख 15 हजार 691 इक्विटी शेयरों के मुकाबले 7 करोड़ 38 लाख 73 हजार 206 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा उत्साहजनक रहा, जो 3.79 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं योग्य संस्थागत खरीदारों की श्रेणी में भी मजबूत भागीदारी देखने को मिली और यह हिस्सा 2.91 गुना भर चुका है। हालांकि खुदरा निवेशकों की भागीदारी अपेक्षाकृत धीमी रही और यह श्रेणी अभी 0.83 गुना सब्सक्रिप्शन पर है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम दिन तक इसमें भी तेजी आ सकती है।

यह आईपीओ 12 दिसंबर को निवेश के लिए खुला था और 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। करीब 10,602.65 करोड़ रुपये के इस बड़े निर्गम में लगभग 4.90 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई है। यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल के रूप में लाया गया है, यानी इससे जुटाई जाने वाली राशि कंपनी के पास न जाकर मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी। निर्गम संरचना के तहत 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए, 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए और 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की मजबूत कारोबारी स्थिति इस आईपीओ की लोकप्रियता का बड़ा कारण मानी जा रही है। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के आधार पर यह कंपनी देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का बाजार हिस्सा 13.3 प्रतिशत रहा है, जो इसकी मजबूत पकड़ और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड उद्योग के विस्तार और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए बाजार जानकार इस आईपीओ को लेकर आशावादी नजर आ रहे हैं। इसी वजह से शुरुआती दिनों में ही इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आने वाले दिनों में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को धनशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

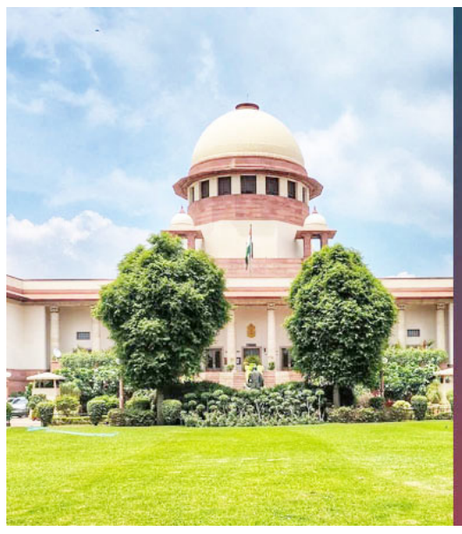

(जीएनएस)। नई दिल्ली। गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए कथित धनशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत प्रदान की। यह मामला अहमदाबाद में कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है और पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान अवैध तरीके से पैसे की उगाही की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए और पत्रकार सुनवाई के दौरान किसी भी तारीख बढ़ाने की मांग न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ यह भी साफ किया कि लांगा इस मामले के संदर्भ में अखबार में कोई लेख या टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने चेताया कि यदि आदेश का उल्लंघन हुआ, तो उनकी जमानत रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने साथ ही ईडी को निर्देश दिया कि वे जमानत की शर्तों के पालन पर नियमित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लांगा फिलहाल कानूनी सुरक्षा के तहत हैं, लेकिन मामले की जांच अब अगले चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही गवाहों के बयानों तथा सबूतों के आधार पर जांच प्रक्रिया और तीव्र होने की संभावना है।

ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पत्रकार द्वारा पैसे की उगाही करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, पत्रकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा और कहा कि जमानत मिलना जरूरी है क्योंकि मामले में जांच अभी चल रही है और पत्रकार के खिलाफ आरोप अब तक निश्चित नहीं हुए हैं।

इस मामले में अब तक नौ गवाहों को नामित किया गया है। इससे पहले 31 जुलाई 2025 को गुजरात हाईकोर्ट ने लांगा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि जमानत मिलने से अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंच सकता है। लांगा को पहली बार 25 फरवरी 2025 को कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2024 में उन्हें जीएसटी धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले ने पत्रकारिता और वित्तीय जांच एजेंसियों के बीच कानूनी टकराव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जमानत से लांगा फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन अगले महीनों में गवाहों के बयान, बैंकिंग लेन-देन की जांच और वित्तीय सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है। इस मामले की जांच न केवल वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता के लिए अहम है, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवालों को भी सामने लाती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और ईडी की टीम लगातार जुड़े सबूतों का विश्लेषण कर रही है। जांच में फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, निवेशकों के बयान और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामला कई महीनों तक जांच में रहेगा और उसके बाद ही कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। ऐसे में यह जमानत लांगा के लिए फिलहाल राहत भरी है, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी चुनौतियां बरकरार रहेंगी।

यह मामला देश में पत्रकारिता और वित्तीय मामलों की निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में आरोपियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन जांच और गवाहों के सबूतों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने की जिम्मेदारी न्यायालय की होगी।

उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा रहा

(जीएनएस)। फूलपुर। मीरा-भायंदर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुर पर बिल्डर समय चौहान की हत्या का आरोप है, जो मुंबई के विरार क्षेत्र में 26 फरवरी 2022 को गोली मारकर की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के शुरू से ही सुभाष ठाकुर को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में माना जा रहा था, और अब मीरा-भायंदर पुलिस ने उसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार सुभाष सिंह ठाकुर लंबे समय तक फतेहपुर जेल में बंद था, लेकिन जेल के भीतर से ही उसने अपने आपराधिक नेटवर्क और गैंग के संचालन का काम जारी रखा। वह मुंबई के कुख्यात जे जे शूटआउट केस में भी मुख्य आरोपी रहा है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी माना जाता था। दाऊद की बहन के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या के बाद सुभाष ने दाऊद के कहने पर हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी, जिससे उसकी दाऊद के साथ नजदीकी और भरोसा स्थापित हुआ।

हालांकि, 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद और सुभाष के रिश्ते में दूरी आ गई। इसके बावजूद सुभाष ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए रखी और लंबे समय तक मुंबई और उत्तर भारत में अपने अपराध नेटवर्क को सक्रिय रखा।

सुभाष सिंह ठाकुर वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव का रहने वाला है। वह एक पुलिस अधिकारी का बेटा था। 1990 के दशक में काम की तलाश में वह मुंबई गया और वहां बिल्डरों और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने लगा। धमकाने और हथियार का इस्तेमाल करने में माहिर सुभाष ने देखते ही देखते सुपारी किलर के रूप में अपनी पहचान बनाई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुभाष सिंह का गिरफ्तार होना अंडरवर्ल्ड और उनके वित्तीय लेन-देन पर गंभीर चोट है। इस गिरफ्तारी से दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में भी भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। मीरा-भायंदर पुलिस अब इस मामले में जुड़े अन्य सहयोगियों और घटनाओं की जांच तेज कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुभाष ठाकुर जैसी फिगर की गिरफ्तारी से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के रहस्यों और आपसी कनेक्शन का पर्दाफाश होने की संभावना भी बढ़ गई है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि सुभाष सिंह ठाकुर से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है, जो समय पर और व्यापक जांच को मजबूत करने में मदद करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि लंबे समय तक छिपे अपराधी भी कानूनी कार्रवाई के सामने नहीं टिक पाते और कानून अपना काम करता है। मीरा-भायंदर पुलिस ने इस कार्रवाई को अपने लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, अयोध्या में होगा अंतिम संस्कार

(जीएनएस)। अयोध्या। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक और राम मंदिर के निर्माण में सक्रिय योगदान देने वाले प्रख्यात संत एवं पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा सुपर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से अयोध्या, संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर आज अयोध्या लाया जाएगा और मंगलवार 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आश्रम हिंदू धाम में श्रद्धालु और अनुयायी पहुंच रहे हैं।

डॉ. वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को रीवा के गुढ़वा गांव में हुआ। मात्र 12 वर्ष की उम्र में वे अयोध्या आ गए और वहीं अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। अपने जीवनकाल में उन्होंने रामकथा का वाचन, समाजसेवा और धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था और वे मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शुमार थे।

उनकी अंतिम यात्रा हिंदू धाम से शुरू होगी और राम मंदिर तक जाएगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता और धार्मिक प्रतिनिधि उपस्थित होने की संभावना है। उनके शिष्य और उत्तराधिकारी महंत डॉ. राघवेशदास ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर आज देर शाम तक अयोध्या पहुंचेगा।

डॉ. वेदांती ने 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया और अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत में उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने किसी मस्जिद को नहीं बल्कि मंदिर के खंडहर को हटाया था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था।

संत समाज और राजनीतिक क्षेत्र में डॉ. वेदांती की उपस्थिति सदैव महत्त्वपूर्ण रही। वे मछलीशहर सीट से दो बार भाजपा सांसद रहे और अयोध्या में रामकथा वाचन तथा धर्म प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। वे संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे और हनुमानगढ़ी के महंत तथा राम मंदिर उद्धारक महंत अभिराम दास के शिष्य थे। उनका वशिष्ठ भवन नामक आश्रम अयोध्या में स्थित है, जहां उन्होंने दशकों तक रामकथा का आयोजन किया। उनके निधन से अयोध्या और देशभर में संत समाज, भक्त और राजनैतिक गलियारे गहरे शोक में हैं। श्रद्धालु उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आश्रम और अंतिम यात्रा स्थल पर इकट्ठा होंगे। डॉ. वेदांती का योगदान न केवल राम जन्मभूमि आंदोलन तक सीमित रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक चेतना फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनका व्यक्तित्व आज भी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बना हुआ है।

उनकी अंतिम यात्रा अयोध्या में एक भव्य और श्रद्धासूचक समारोह के रूप में आयोजित होगी, जहां देशभर से अनुयायी और भक्त उनके जीवन, शिक्षाओं और योगदान को याद करेंगे। डॉ. वेदांती की विरासत अयोध्या और पूरे देश में धार्मिक जागरूकता, संत समाज की भूमिका और राम मंदिर निर्माण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के रूप में सदैव जीवित रहेगी।

प्राप्त ज्ञान का उपयोग देश और समाज के विकास में करें: उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पारुल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में किया संदेश

(जीएनएस)। वडोदरा। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में सोमवार को पारुल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के विभिन्न संकायों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें प्रेरित किया।

अपनी अध्यक्षीय वक्तव्य में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि आज के युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें नौकरी देने और नए उद्यम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को यह संदेश भी दिया कि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करना चाहिए। संघवी ने युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और देश के लिए नई उपलब्धियों के रास्ते खोल सकते हैं। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी उपस्थित रहीं। ओलंपिक बॉक्सर मेरी कॉम, टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा, सफल बिजनेस वुमन विनिता सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने, आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम ऊँचा करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुशासन, मेहनत और लगन सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं।

दीक्षांत समारोह में पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट देवांशु पटेल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण स्टाफ, विद्यार्थी और उनके परिजन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने उत्साह और जोश के साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया। विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया गया कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के कल्याण में योगदान देने की क्षमता विकसित करने का सबसे सशक्त माध्यम है।

समारोह का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना था। उप मुख्यमंत्री संघवी ने युवाओं को यह भी याद दिलाया कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े समुदायों के विकास में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यही सच्ची शिक्षा का महत्व है, जो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करती है।

यह दीक्षांत समारोह पारुल यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके परिवारों के लिए प्रेरणा और गर्व का अवसर था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे अपने ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग देश और समाज के विकास में करेंगे, जिससे भारत का भविष्य और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके।

गुजरात में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सीआईडी क्राइम इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

(जीएनएस)। गांधीनगर। गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीआईडी क्राइम के इंस्पेक्टर पेथा पटेल और कांस्टेबल विपुल देसाई को 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सरगासन इलाके में तब की गई, जब दोनों आरोपी रिश्वत की रकम लेने के दौरान पकड़े गए।

मामला तब सामने आया जब कॉल सेंटर से जुड़े एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का कहना था कि सीआईडी क्राइम के ये अधिकारी उसके खिलाफ केस में कोई कानूनी कार्रवाई न करने के बदले 30 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस पर आरोपी ने रिश्वत देने से इंकार कर सीधे एसीबी को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद एसीबी ने ट्रैपिंग योजना बनाई। इंस्पेक्टर डीएन पटेल को ट्रैपिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। योजना के अनुसार रिश्वत की रकम देने और लेने की मुलाकात गांधीनगर के स्वागत सिटी मॉल के पास हरि ग्रुप साइट के नजदीक सड़क पर तय की गई।

जैसे ही आरोपी ने 30 लाख रुपये कांस्टेबल को सौंपे, एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके बाद इंस्पेक्टर पेथा पटेल को भी हिरासत में लिया गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। इस कार्रवाई ने गुजरात पुलिस में हड़कंप मचा दिया है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अधिकारियों की सजगता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई नागरिकों में विश्वास बढ़ाती है। इस गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी पूरी तरह सतर्क है। गुजरात में यह कदम अन्य अधिकारियों के लिए चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी दोनों आरोपी एसीबी की हिरासत में हैं और उनकी संपत्ति, वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क की पूरी जांच की जाएगी। यह मामला राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की तत्परता और कार्रवाई की गंभीरता को उजागर करता है।

महंगाई में मामूली गिरावट, थोक महंगाई दर नवंबर में -0.32 फीसदी पर पहुंची

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। नवंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित थोक महंगाई दर घटकर -0.32 फीसदी पर आ गई, जबकि अक्टूबर में यह -1.21 फीसदी थी। पिछले वर्ष नवंबर 2024 में यह 2.16 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी।

विश्लेषकों के अनुसार इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं के उत्पादन और बिजली जैसी वस्तुओं की कीमतों में कमी रही। नवंबर में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर 4.16 फीसदी रही, जबकि अक्टूबर में यह 8.31 फीसदी थी। सब्जियों की कीमतों में भी गिरावट आई और महंगाई दर घटकर 20.23 फीसदी रह गई, जो अक्टूबर में 34.97 फीसदी थी।

महंगाई में गिरावट की खबर के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में नीतिगत दरों में भी ढील दी है। इस महीने की शुरुआत में RBI ने रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया था। वहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर नवंबर में मामूली बढ़त के साथ 0.71 फीसदी पर पहुंच गई, जो अक्टूबर में 0.25 फीसदी थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि थोक महंगाई दर में गिरावट आम जनता के लिए राहत की संकेत है, क्योंकि इससे बाजार में कीमतों पर स्थिरता बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही RBI की दरों में कटौती से कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि मौसमी और वैश्विक कारक आने वाले महीनों में महंगाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता आवश्यक है।

इस दौरान, घरेलू स्तर पर दाल, आलू और प्याज जैसी प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी ने आम लोगों की जेब पर सकारात्मक असर डाला है। इससे बाजार में खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ता खर्च में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

आंकड़ों के अनुसार दालों की कीमतों में नवंबर में 15.21 फीसदी की कमी आई, जबकि आलू और प्याज की कीमतें क्रमशः 36.14 फीसदी और 64.70 फीसदी घट गईं। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर भी 1.33 फीसदी पर आ गई, जो अक्टूबर में 1.54 फीसदी थी। ईंधन और बिजली की महंगाई दर 2.27 फीसदी रही, जबकि अक्टूबर में यह 2.55 फीसदी थी।

लखनऊ से अहमदाबाद तक अकेले साइकिल चला 11 साल का बच्चा, तीन दिन बाद मिला सुरक्षित

(जीएनएस)। लखनऊ। कभी-कभी छोटी-सी डांट बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के इंदिरानगर से सामने आया है, जहां 11 साल का एक बच्चा अपनी मां की फटकार से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गया और तीन दिन बाद करीब 1100 किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस द्वारा बरामद किया गया। यह घटना बच्चों की भावनाओं की नाजुकता और उनकी साहसिक प्रवृत्ति को एक बार फिर उजागर करती है।

बच्चे के पिता बृजेश कुमार सुमन पटेलनगर, इंदिरानगर में शिक्षक हैं। उनका बेटा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल, सेक्टर-8 में कक्षा 6 में पढ़ता है। 10 दिसंबर को स्कूल से लौटने के बाद मां ने किसी मामूली बात पर उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर बच्चा दोपहर करीब 3 बजे अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर निकल गया। परिवार को शुरू में यह अंदाजा नहीं था कि वह घर छोड़ देगा। जब देर शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की और रात में गाजीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

बृजेश कुमार सुमन ने पुलिस को बच्चे की हालिया तस्वीर, कपड़ों का विवरण और अन्य जानकारी दी। लखनऊ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बच्चे का विवरण शहर और आसपास के थानों-जिलों में साझा किया गया और नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पुलिस व ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर भी अपलोड किया गया।

तीन दिन बाद अहमदाबाद पुलिस को बच्चे की बरामदगी हुई। नेशनल पोर्टल पर बच्चे का विवरण मैच किया गया और 13 दिसंबर की सुबह लखनऊ पुलिस से संपर्क किया गया। गाजीपुर थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है।

बच्चे के लखनऊ से अहमदाबाद तक कैसे और किन साधनों से पहुंचा, यह फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। लखनऊ पुलिस की एक टीम अब परिवार के साथ अहमदाबाद रवाना हो गई है ताकि बच्चा जल्द अपने घर लौट सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के साथ छोटे-मोटे व्यवहारिक विवाद में प्यार और समझदारी से संवाद करना चाहिए, ताकि वे ऐसे जोखिमपूर्ण कदम न उठाएं। परिवार वाले अब राहत की सांस ले रहे हैं और बच्चे की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि बच्चों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना कितना जरूरी है।

बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कलोल स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 12216/12215 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कलोल स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

16 दिसम्बर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन कलोल स्टेशन पर 20:11 बजे पहुँचेगी तथा 20:13 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार, 16 दिसम्बर, 2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन कलोल स्टेशन पर 22:41 बजे पहुँचेगी तथा 22:43 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

वडोदरा मंडल द्वारा ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए किया गया जागरूक

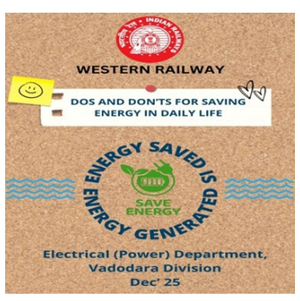

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में, वडोदरा मंडल द्वारा 08 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2025 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सभी रेल कर्मचारी एवं अधिकारीगणों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण के महत्व को रेलकर्मियों एवं जन-जन तक पहुँचाने हेतु विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाते हुए मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर लोगो को जागरूक करने के लिए ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पोस्टर लगाए गए। मंडल मुख्यालय में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें वडोदरा मंडल के अधिकारीगण सम्मिलित होकर लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, रेलवे द्वारा आवंटित मोबाइल सिम कार्डों पर ऊर्जा संरक्षण आधारित कॉलर ट्यून (रिंगटोन) के माध्यम से रेलकर्मियों में जागरूकता फैलाने का सफल प्रयास किया गया।

श्री सक्सेना ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित "क्या करें / क्या न करें" विषयक सुझावों के साथ एक संक्षिप्त पत्रिका प्रकाशित कर रेल कर्मचारी एवं अधिकारीगणों के बीच जागरूकता हेतु वितरित की गई।

वडोदरा मंडल ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ भविष्य में भी ऐसे सतत एवं प्रभावी उपाय अपनाता रहेगा।